AN HON. MEMBER: Cost of production?

SHRI T. A. PAI: You would require Rs. 4 lakhs for a unit to manufacture 4,000 tonnes of deformed bars. The difference will be about Rs. 250 per tonne between ordinary steel and this. It will work out to an investment of Rs. 1,000 per tonne.

Survey of industries in and around Bokaro Steel Ltd. by R.P.F.C., Patna

*366. SHRI R. P. YADAV: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether any survey has been conducted by the Regional Provident Fund Commissioner, Patna for the purposes of examining the applicability of the Employees' Provident Funds Act, 1952 to industries set up in and around Bokaro Steel Ltd. in Bokaro (District Dhanbad);

(b) if so, the particulars of the factories covered under Section 1(3) of the Act; and

(c) the factories listed in the Infant and Marginal registers and the establishments inspected under Section 2A of the Act?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA): (a) and (b). The Provident Fund authorities have reported as under:—

(a) Yes, Sir.

(b) The following three factories/establishments have been covered under section 1(3) of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act:

(i) M|s. Consolidated Engg. Co. (P) Ltd., Bokaro Steel City, Bakaro.

(ii) M/s Bridge & Roof Co. India Ltd., Bokaro Steel City P.O. Dhanbad.

(iii) M/s Garden Reach Workshop Ltd., Bokaro Steel City, Dhanbad.

(c) A list of factories/establishments listed in infant and marginal registers and the establishments inspected under Section 2A of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act as furnished by the Provident Fund Authorities is laid on the Table.

Statement

Factories/establishments, listed in infant and marginal registers and the establishments inspected under Section 2A of the Employee's Provident Funds and Family Pension Fund Act.

Sl. No.	Name of Establishment/Factory
1	Textile Machinery Construction Ltd. Bokaro Steel City, Bokaro
2	Damodar Enterprises Bokaro Steel City, Bokaro
3	Central India Machinery Mfg. Co Ltd., Bokaro Steel City Bokaro
4	Modern India Construction Co Ltd., Bokaro Steel City, Bokaro;
5	New Standard Engineering Works, Bokaro Steel City, Bokaro
6	Bokaro Hotel, Bokaro Steel City, Bokaro
7	Arvind Construction Co. Ltd., Bokaro Steel City, Bokaro;
8	Alpana Cinema, Bokaro Steel City, Bokaro
9	Hindustan Structure Construction Co Ltd., Bokaro Steel City Bokaro (A Govt. of India Undertaking H. O. Calcutta. 22)
10	Gammans Ltd., Bokaro Steel City, Bokaro H. O. Bombay

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, अफ़सरशाही की यह बड़ी घिनौनी तस्वीर है पटना प्रोवीडेंट फंड कमिशनर के रूप में और उन के बड़े बाबू के रूप में। यह बात सदन में भी उठायी गई और मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उन दोनों का तबादला किया। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी उन के खिलाफ जो चार्जेज़ आये थे उन पर कोई इनक्वायरी कराने जा रहे हैं जिस से जो उन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग किया और जो उन के चलते प्रोवीडेंट फंड ऐक्ट के अन्दर फ़ैक्ट्रीज़ कवर नहीं हो पायीं इसलिए उन के खिलाफ़ कायवाही की जा सके ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : हम लोग देख रहे हैं और जैसा आवश्यक होगा कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने एक लिस्ट दी है जिस के मुताबिक प्रोवीडेंट फंड ऐक्ट के अन्दर वे सब फ़ैक्ट्रीज़ कवर होती हैं। तो क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस के अलावा और कौन सी फ़ैक्ट्रीज़ हैं धनबाद के आसपास जो प्रोडक्शन में चली गई हैं और अभी तक जिन पर प्रोवीडेंट फंड ऐक्ट लागू नहीं हुआ है ? यदि नही हुआ है तो कब तक लागू होगा ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : ये कुछ इन्फ़ैंट फ़ैक्ट्रीज़ हैं, मार्जिनल हैं जो रजिस्टर में दर्ज की गई हैं। अभी उन के ऊपर यह एक्ट बांधा नहीं है। उन का सर्वे करा लिया है, और तीन साल, पांच साल की अवधि बीत जाने के बाद उन पर लागू करेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : कौन कौन फ़ैक्ट्रीज़ हैं जो प्रोडक्शन में चली गई हैं और जिन पर ऐक्ट नहीं लागू हुआ है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : ये सभी फ़क्ट्रीज़ प्रोडक्शन में चली गई हैं लेकिन अभी हम ने उन के ऊपर यह ऐक्ट लागू नहीं किया है क्योंकि तीन साल, पांच साल की अवधि पूरी नहीं हुई है। तीस फ़ैक्ट्रीज़ हैं जिनके मैंने नाम बताये—मैसर्ज कंसौलीडेटेड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बोकारो, मैसर्स ब्रिज एंड रूफ़ कम्पनी इंडिया लिमिटेड और मेसर्स गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड। यह तीन फ़ैक्ट्रीज़ हैं, और इन के अलावा एक और कम्पनी है जो उस रूप में नहीं है बल्कि एक ब्रान्च है एक कम्पनी की, उस पर भी लागू हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर को नया रूप देना

*369. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर को बदलती हुई वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नया रूप दिलाने के लिए कोई उपयुक्त कदम उठा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) and (b). The Government of India has supported steps to amend the UN Charter to conform to the changing situation, such as the enlargement of the Security Council and the Economic and Social Council. Government believes that the UN Charter must evolve with the times in order to remain an effective and dynamic force for peace and progress, and shares the understandable desire for a comprehensive review. It is of the opinion, however, that the prevailing climate of international politics is not conducive to a general review of the UN Charter, a question which has been on the Agenda of the UN General Assembly for several years now.

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष जी, हमारे देश की प्रधान मंत्री और नेताओं ने नान-ऐलाइन्ड कानफरेंस में हिस्सा लिया, 50, 60, 70 देश उस में आये, और अभी कामरेड ब्रैझनेव साहब आये, तो क्या इन मीटिंगों में कभी यह जिक्र हुआ कि यू० एन० चार्टर में सुधार किया जाय ? अभी मंत्री जी ने कहा